तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड

बनाम

वेस्टर्न जीको इंटरनेशनल लिमिटेड

(सिविल अपील सं. 3415/2007)

सितंबर 04,2014

[टी. एस. ठाकुर, सी. नागप्पन, आदर्श कुमार गोएल, न्यायाधिपतिगण]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 – धारा 34 – मध्यस्थ पंचाट को रदद करने के लिये आवेदन – अपीलकर्ता – निगम द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में अनुबंध का पुरस्कार जिसके तहत जहाज को आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्य करने के लिये प्रतिवादी को सौंप दिया गया – जहाज को निर्धारित तिथि पर अपीलकर्ता को वापस नहीं किया जा सका – अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किया गया – अतिरिक्त निहित शुल्क के लिये कुछ राशि की कटौती, कर कानून में बदलाव, आयकर सहित मूल्य शुल्क में सुधार – पक्षकारो के बीच विवाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित – न्यायाधिकरण का मानना है कि 21.10.2001 के बाद की देरी के लिये प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, कि अपीलकर्ता द्वारा 01.11.2001 से 22.03.2002 तक अतिरिक्त निहित शुल्क की कटोती उचित नहीं है, साथ करो के कारण कटौती – अपीलकमर्ता द्वारा धारा 34 के तहत

याचिका कि यह पंचाट धारा 34(2(बी)(आई) के अंतर्गत भारत की सावर्जनिक नीति के साथ टकराव में है – हालांकि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया, खंडपीठ द्वारा आंशिक रूप से लंबित और भविष्य के ब्याज को दिये गये पुरस्कार से हटा दिया गया – अपील पर अभिनिर्धारित किया : यदि मध्यस्थ अपने सामने साबित किये गये तथ्यो पर कोई निष्कर्ष निकालने में विफल रहते है जो निकाला जाना चाहिये था या यदि उन्होने एक ऐसा निष्कर्ष निकाला है जो अस्थित है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, तो निर्णय चुनौती के लिये खुला होगा – तथ्यो पर, मध्यस्थो ने अपीलकर्ता-निगम को 21.10.2001 के बाद की देरी के लिये जिम्मे्दार ठहराने में गलती की, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हत्या हुई, वे इस तरह के सिद्ध तथ्यो की तार्किक रूप से निकलने वाले निष्कर्षो की सराहना करने और निष्कर्ष निकालने में भी विफल रहे । 4 महीने और 232 दिनो की अवधि में से, जो मध्यस्थो ने अपीलकर्ता को दी थी, 56 दिनो की अवधि कम कर दी गई – उक्त अवधि के लिये अपीलकर्ता द्वारा की गई कटैतियां बरकरार रखी गई – मध्यस्थो द्वारा दिये गये फैसले को उस सीमा तक संशेधित किया गया ।

अपील को स्वीकार करते हुये न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 उन्नयन के बाद जहाज को निगम को लौटाने में 9 जुलाई 2001 ये 6 मई 2002 तक 9 महीने और 28 दिनो की देरी हई 1.11.2001 से

22.03.2002 के बीच की अवधि के संबंध में जो 4 महीने और 22 दिनो की होती है, मध्यस्थो ने देरी के लिये अपीलकर्ता निगम को जिम्मेदार पाया है। मध्यस्थो ने माना कि लाईसेंस जारी करने के लिये अमेरिकी अधिकारियो को कोई औपचारिक आवेदन किया जाना चाहिये या नहीं, यह निर्णय लेने में देरी और प्रतिवादी द्वारा प्राप्त औपचारिक अस्वीकृति केवल अपीलकर्ता निगम के लिये जिम्मेदार थी। प्रथम अंतराल के लिये अपीलकर्ता द्वारा की गई कटौती, जिसमें 1 नवंबर, 2001 और 25 नवंबर 2001 के बीच की अवधि शामिल है, दोनो दिन शामिल है, इसलिये बरकरार नहीं रखी जा सकती है और उस सीमा तक मध्यस्थ पंचाट को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरे अंतराल में 26 नवंबर, 2001 के बीच की अवधि शामिल है – वह तारीख जब अपीलकर्ता निगम ने लाईसेंस देने के लिये औपचारिक आवेदन करने के लिये निर्देश जारी किये और 8 जनवरी, 2002 जब ऐसा आवेदन वास्तव में प्रतिवादी कंपनी द्वारा किया गया था, प्रतिवादी दावेदार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये। न्यायाधिकरण इस पहलू की सराहना करने में विफल रहा, इस प्रकार, एक स्पष्ट त्रुटि हुई जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हो गया। 8 जनवरी, 2022 और 8 मार्च, 2002 के बीच की अवधि, जिसमें तीसरा अंतराल शामिल है, जिसके दौरान अमेरिकी अधिकारियो ने निर्णय िलया कि लाईसेंस देने के लिये अावेदनको अपीलकर्ता निगम के खिलाफ सही तरीकेसे गिनागया है क्योंकि यह निगमके कहने पर था कि एक औपचारिक

आवेदन किया गया। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने सही कहा कि इस अवधि के लिये कटौती उचित नहीं थी। ऐसा कोई वैध कारण नहीं है कि चौथे अंतराल में 8 मार्च 2002 और 22 मार्च 2002 के बीच की अवधि शामिल हो, जब आवेदन की अस्वीकृति अपीलकर्ता निगम को बताई गई थी, उसे प्रतिवादी के खिलाफ नहीं गिना जाना चाहिये, जो वास्तव में अपीलकर्ता को अस्वीकृति के बारे में सूचित कर सकता था, ऐसा करने में लगभग दो सप्ताह लगने के बजाय। [पैरा 18,20,21,23] [15-सी-डी, 17-बी-एच; 18-बी-डी, एफ]

1.2 . अभिव्यक्ति 'भारतीय कानून की मौलिक नीति' में ऐसे सभी मौलिक सिद्धांत शामिल है जो इस देश में न्याय प्रशासन और कानून को लागू करने के लिये आधार प्रदान करते है। तीन विशिष्ट और मौलिक न्यायिक सिद्धांत यह है कि प्रतयेक निर्णय में चाहे वह न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा हो जो किसी नागरिक के अधिकारो को प्रभावित करता है या किसी नागरिक परिणाम की ओर ले जाता है, संबंधित न्यायालय या प्राधिकरण मामले में न्यायिक दृष्टिकोण अपनाने के लिये बाध्य है। वे मनमाने, मनमौजी या सनकी तरीके से कार्य नहीं कर सकेते। न्यायिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि प्राधिकारी सदभावनापूर्णक कार्य करता है और विषय मे निष्पक्ष, उचित और वस्तुनिष्ठ तरीके से निपटता है और उसका निर्णय किसी भी बाहरी विचार से प्रेरित नहीं होता है। दूसरा सिद्धांत

यह है कि एक न्यायालय और एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी को भी अपने समक्ष पक्षो के अधिकारो और दायित्वो का निर्धारण करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के अनुसार ऐसा करना चाहिये। मामले पर निर्णय लेने वाले न्यायालय/प्राधिकारण को एक या दूसरे तरीके से विचार करते समय अपने दिमाग को संबंधित तथ्यो और परिस्थितियो पर लागू करना चाहिये, जो कि न्यायालय या प्राधिकरण जो निण्रय ले रहा है उसके समर्थन में कारणो को दर्ज करके सबसे अच्छा किया जाता है। तीसरा सिद्धांत यह है कि एक निर्णय जो विकृत या इतना तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर नहीं पहुंचा होगा, उसे अदालत में कायम नहींरखा जा सकेगा। निर्णयो की विकृति अथवा अतार्किकता परीक्षण वेडनसबरी के तर्कसंगतता के सिद्धांत की कसौटी पर परखा जाता है। [पैरा 26,28, 29] [21 - एच; 22-ए-सी, ई; 23-एफ-जी; 24-बी-सी]

1.3 . यदि उनके समक्ष साबित तथ्यों पर मध्यस्थ एक निष्कर्ष निकालने में विफल रहते हैं जो निकाला जाना चाहिए था या यदि उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है जो इसके सामने है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि होती है, यहां तक कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किये जाने पर भी निर्णय जो पर्याप्त स्वतंत्रता का आनंद लेता है और पंचाट बनाने में जोडो को खेलता है, उसे चुनौती दी जा सकती है और उसे हटा दिया जासकता है या संशोधित किया

जा सकता है, यह इस बात पर निर्भरकरता है कि अपमानजनक हिस्सा बाकी हिस्सों से अलग है या नहीं। [पैरा 30] [24-ई-एफ]

1.4 . मध्यस्थों ने देरी के लिये अपीलकर्ता निगम को जिम्मेदार ठहराने के उददेश्य से 16 अक्टूबर, 2001 और 21 मार्च, 2002 के बीच की पूरी अवधि को एक साथ जोड़ दिया, उन्होने एक गलती की जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हत्या हुई, इस तथ्य के अलावा कि वे इसकी सराहना करने और निष्कर्ष निकालने में विफल रहे। वह तार्किक रूप से ऐसे सिद् तथ्यो से प्रवाहित होता है। मध्यस्थो ने ठीक ही कहा कि आयकर अधिनियम के तहत कोई कर देय नहीं हे। उस सीमा तक पंचाट को दी गई चुनौती अस्वीकार की जाती है। 4 महीने और 22 दिनो की अवधि में से, जो मध्यस्थो ने अपीलकर्ता को दी है, 56 दिनो की अवधि जिसमें पहले अंतराल के 42 दिन और दूसरे अंतराल के 14 दिन शामिल है, कम कर दी जायेगी। अपीलकर्ता निगम द्वारा 56 दिनो की उक्त अवधि के लिये की गई कटौतियो की पुष्टि की जाती है और मध्यसथो द्वारा दिये गये फैसले को प्रतिवादी को देय राशि में आनुपातिक कमी के साथ उस सीमा तक संशोधित किया जाता है। [पैरा 23,31,32,33] [18-F-G; 24 एफ-जी; 25-बी-एच]

ओ. एन. जी. सी. लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड 2003 (3) एससीआर 691: (2003) 5 एस. सी. सी. 705; ए. सी. कंपनीज लिमिटेड बनाम पी. एन.

शर्मा और अन्य, 1965 एससीआर 366: ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1595 – संदर्भित किया गया।

रिज बनाम बाल्डविन 1963 2 ऑल ई. आर. 66 – संदर्भित किया गया।

2003 (3) एससीआर 69 संदर्भित किया गया पैरा 25

1963 2 सभी ईआर 66 संदर्भित किया गया पैरा 26

1965 एससीआर 366 संदर्भित किया गया पैरा 27

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 3415 / 2007

अपील संख्या 24/2006 अंतर्गत मध्यस्थता याचिका संख्या 203 / 2005 में बॉम्बे उच्च न्यायालय, निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.2.2006 से।

पारस कुहाड़, जितिन चतुर्वेदी, प्रणिता शेखर, अभिक चिमनी, स्वाति, सोमिरन शर्मा, विष्णु शर्मा, के. आर. शशिप्रभु अपीलार्थी के लिए ।

एन. गणपति, मनप्रीत लांबा, प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय टी. एस. ठाकुर, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

1. यह अपील 10 फरवरी 2006 के एक आदेश से उत्पन्न हुई है जो बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित किया गया था, जिसके द्वारा अपीलकर्ता निगम द्वारा दायर ओएसए नंबर 24/2006 को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और मध्यस्थता याचिका संख्या 302/2005 में उच्च

न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को इस संशोधन के साथ पुष्टि की गई कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा विचाराधीन राशि और भविष्य के ब्याज का पंचाट हटा दिया जाएगा।

2. अपीलार्थी-निगम तेल और प्राकृतिक गैसों की खुदाई और अन्वेषण के व्यवसाय में लगा लगा हुआ है। नवंबर 1999 में, अपीलार्थी ने भूकंपीय सर्वेक्षण पोत, एम. वी. के तकनीकी उन्नयन के लिय प्रस्ताव आमंत्रित किये। सागर संधानी (इसके बाद इसे पोत के रूप में संदर्भित किया गया है) को आधुनिकीकरण की दृष्टि से। निविदा शर्तों के अनुसार, पोत के उन्नयन के लिये आवश्यक उपकरणो की मुख्य वस्तुओं में से एक "हाइड्रोफोन से सुसज्जित स्ट्रीमर था। हालांकि विनिर्देशो में ऐसे हाइड्रोफोन की उत्पत्ति का उल्लेख नहीं किया गया है।

3. निविदा सूचना के जवाब में प्रत्यर्थी-मेसर्स वेस्टर्न गेको इंटरनेशनल लिमिटेड ने अमेरिकी मूल के "जियोप्वाइंट" हाइड्रोफोन से लैस नेसी 4 स्ट्रीमर्स की आपूर्ति के लिए एक बोली प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अपीलार्थी का मामला यह है कि ऐसे जियोप्वाइंट हाइड्रोफोन की आपूर्ति से संबंधित शब्द प्रतिवादी-कंपनी द्वारा किए गए प्रस्ताव का एक भौतिक हिस्सा था। जिसके पक्ष में अपीलार्थी-निगम ने अंततः 10 अक्टूबर, 2000 के अपने पत्र के अनुसार एक अनुबंध प्रदान किया, जिसे 25 अक्टूबर 2000 को विधिवत स्वीकार किया गया था। प्रस्तावित आधुनिकीकरण और

उन्नयन कार्य को आगे बढाने के लिय पोत को 10 अप्रैल, 2001 को प्रतिवादीकोसौंप दिया गया । 18 जून, 2001 को पक्षकारो के बीच एक औपचारिक अनुबंध निष्पादित किया गया ।

4. यह आम आधार है कि अमेरिकी मूल के "जियोप्वाइंट" हाइड्रोफोन अनुबंध के अनुसारपोत में पोत में लगाए गए थे और उनका परीक्षण भी किया गया था। फिर भी जहाज को 9 जुलाई, 2001 को अपीलकर्ता को वापस नहीं सौंपा जा सका,जो उस उददेश्य के लिय नियत तारीख थी, क्योंकि प्रतिावदी को ऐसे हाइड्रोफोन की बिक्री के लिये अमेरिकी अधिकारियो से लाईसेंस प्राप्त करने में कुछ समस्या का सामना करना पडा था। अपीलकर्ता निगम का दावा है कि प्रतिवादी ने पहली बार अमेरिकी अधिकारियों को 1 अगस्त, 2001 को आवेदन किया था, यानि निगम को पाते की डिलीवरी की नियत तारीख के लगभग एक महीने बाद। निगम द्वारा उसे सूचित किये जाने के अनुसार लाईसेंस के अनुरोध को कोई औपचारिक अस्वीकृति नहीं दी गई क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि मामला प्रतिवादी और अमेरिकी अधिकारियो के बीच किसी प्रकारकी बातचीत के तहत चल रहा था।

5. प्रत्यर्थी का मामला इसके विपरीत यह है कि उसने लाइसेंस प्राप्त करने के अपने प्रयास जारी रखे लेकिन अमेरिका में उसके स्त्रोतो द्वारा सूचित किया गया कि बाद में कुछ कठिन शर्ते लागू होने की संभावना थी,

जिनमें से एक यह हो सकती है कि हमारे द्वारा बनाये गये हाइड्रोफोन का उपयोग केवल ऋण के आधार पर किया जा सकता है, भी केवल 24 महीने की छोटी अवधि के लिये। प्रतिवादी का आगे का मामला यह है कि अमेरिका में उसके स्त्रोत ने उसे सूचित किया था कि अमेरिकी अधिकारियो द्वारा भारत को हाइड्रोफोन बेचने का लाईसेंस देने की संभावना नहीं है। जो भी हो, जब मामला रक्षा विभाग के पास लंबित था, तभी 11 सितंबर, 2001 कोएक बडे आतंकवादी हमले ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से प्रतिवादी की अमेरिका निर्मित हाइड्रोफोन की बिक्री के लिये लाईसेंस पाने की उम्मीद और कम हो गई। प्रतिवादी ने तदनुासर अपीलकर्ता निगम को नये विकास के बारे में सूचित किया और अप्रत्याशित घटना की दलील देते हुये प्रतिवादी ने अपीलकर्ता निगम को जहाज को अमेरिका निर्मित हाइड्रोफोन से लैस करने में असम्र्थता के बारे में सूचित किया। अपीलकर्ता निगम ने 20 सितंबर 2001 के अपने पत्र द्वारा अप्रत्याशित घटनाके आहवान का खंडन किया और प्रतिवादी को सूचित किया कि चूंकि फील्ड सीजन जल्द ही शुरू हो रहा था, इसलिय जहाज की डिलीवरी में किसी भी तरह की देरी से इसके संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रतिवादी ने अपनी ओर से अमेरिका निर्मित हाइड्रोफोन के विकल्प की तलाश और पेशकश शुरू कर दी और अपीकर्ता निगम के साथ तर्क दिया कि चूंकि हाइड्रोफोन की उत्पत्ति का संकेत बोली दसतावेजो में नहीं दिया गया था, इसलिये वह एम- 2 यूएस जियो

स्पेक्ट्रम हाइड्रोफोन द्वारा प्रतिस्थापन का परीक्षण कर रहा था। कनाडाने अपनी नॉर्वे सुविधाओ की उपयुक्तता की जांचकी, जिसे प्रतिवादी ने 27 सितंबर, 2001 तक पूराकरने की उम्मीद की थी। प्रतिवादी ने अपीलकर्ता निगम को सूचित किया कि यदि निगम प्रतिस्थापन स्वीकार करता है तो उन हाइड्रोफोन को थोडे समय के भीतर यूएस हाइड्रोफोन के लिये प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

6. अपीलार्थी-निगम, हालांकि, अनुबंधित हाइड्रोफोन के विकल्प को स्वीकार करने के मूड में नहीं था। इसके विपरीत वह जहाज पर अमेरिका निर्मित हाइड्रोफोन लगवाने को इच्छुक था। इसलिये निगम को प्रतिवादी से अमेरिकी सरकार से लाईसेंस प्राप्त करने के अपने प्रयासो को जारी रखने की आवश्यकता थी, जिस दिशा में अपीलकर्ता निगम ने लाईसेंस प्रापत करने केलिय स्वंय भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से संपर्क किया। प्रस्तावित कनाडाई हाइड्रोफोन के संबंध में अतिरिक्त जानकारी और विवरण निगम द्वारा प्रतिवादी से मांगे गये थे। चूंकि, हालांकि, अमेरिकी सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने के प्रयासों में कोई प्रगति नहीं हो रही थी, प्रतिवादी ने जहाज से अमेरिकी हाइड्रोफोन को हटाने और उन्हें कनाडा में निर्मित हाइड्रोफोन द्वारा प्रतिस्थापन की सुविधा के लिए सिंगापुर में उनकी मरम्मत सुविधा में स्थानांतरित करने के लिए अपीलकर्ता-निगम से मंजूरी मांगी। प्रतिवादी ने 10 अक्टूबर, 2001 को अपीलकर्ता-निगम को विस्तृत पत्र

लिखकर सूचित किया कि अमेरिकी सरकार द्वारा लाइसेंस देने की संभावना नहीं है और उसने अस्वीकृति को रोकने के लिए उस उद्देश्य के लिए किए गए आवेदन को वापस ले लिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 अक्टूबर, 2001 के पत्र द्वारा प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अमेरिकी निर्मित जियोपॉइंट हाइड्रोफोन वाले स्ट्रीमर के साथ जहाज को वितरित करने की स्थिति में नहीं था। इस पत्र के बाद 21 अक्टूबर, 2001 को अपीलकर्ता-निगम को संबोधित पत्र दिया गया, जिसमें अमेरिकी हाइड्रोफोन को हटाने और कनाडाई हाइड्रोफोन के प्रतिस्थापन की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था, जिसका 1999 में एनओआईसी को ईरान परियोजना के लिये दिए गए भूकंपीय सर्वेक्षण पोत की आपूर्ति के संबंध में बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया था। अपीलकर्ता-निगम द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी भी प्रतिवादी द्वारा 24 अक्टूबर, 2001 के पत्र द्वारा निगम को प्रस्तावित प्रतिस्थापन को मंजूरी देने के अनुरोध के साथ प्रदान की गई थी। प्रतिवादी बदले गए हाइड्रोफोन के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त वारंटी देने पर भी सहमत हुआ। 13 नवंबर, 2001 को एक अन्य पत्र द्वारा प्रतिवादी ने अपीलकर्ता-निगम को आश्वासन दिया कि यदि वह प्रतिस्थापन प्रस्ताव पर सहमत होता है तो कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा और कनाडाई हाइड्रोफोन को ठीक करने में शामिल अतिरिक्त लागत भी प्रतिवादी द्वारा वहन की जाएगी।

7. 23 मार्च, 2002 को ही प्रतिवादी सशर्त रूप से अमेरिका निर्मित हाइड्रोफोन के स्थान पर कनाडा में बने हाइड्रोफोन के प्रस्तावित प्रतिस्थापन पर सहमत हो गया। अपीलकर्ता- निगम द्वारा प्रतिस्थापन के लिए लगाई गई शर्तों में से एक धारा 16 के अनुसार परिसमाप्त क्षति की वसूली करने का अधिकार था और विषय अनुबंध के खंड 14 के अनुसार जहाज के अतिरिक्त जुड़ाव के लिए अधिकार था। तदनुसार प्रतिस्थापन हुआ और जहाज अंततः 6 मई, 2002 को कनाडाई हाइड्रोफोन के साथ निगम को वापस सौंप दिया गया। 24 मई, 2002 में, अमेरिकी हाइड्रोफोन के प्रतिस्थापन को दर्ज करने के लिए अनुबंध में एक औपचारिक संशोधन भी किया गया था] जिन्हें कनाडा में बनाया गया था।

8. संशोधित अनुबंध के अनुसार उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्य पूरा होने के बाद, प्रतिवादी ने इसके कारण भुगतान के लिए चालान उठाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अपीलकर्ता-निगम ने अनुबंध के खंड 14 के संदर्भ में अतिरिक्त सगाई शुल्क के लिए अपने बकाया से 5,114,300.98 अमेरिकी डॉलर की कटौती की है।. 20 अगस्त, 2002 को एक अन्य पत्र द्वारा, अपीलकर्ता-निगम ने 4.8% पर लागू कर कानून में बदलाव के आधार पर 410,641.20 अमेरिकी डॉलर की कटौती की, इसके बाद मूल्य शुल्क में सुधार के आधार पर 80,530.10 अमेरिकी डॉलर आयकर की दर 4.8% के साथ कटौती की गई। इन कटौतियों ने उन विवादों को जन्म दिया, जिन्हें भारत

के तीन पूर्व मुख्य न्यायाधीशों वाले एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण में निर्णय के लिए भेजा गया था, जिसके समक्ष प्रतिवादी ने 20 अगस्त की अवधि के लिए मूल बकाया के रूप में 7,327,610.68 अमेरिकी डॉलर और ब्याज के रूप में 1,205,564.13 अमेरिकी डॉलर का दावा 20 अगस्त 2003 से 15 नवंबर, 2003 तक कुल यूएस $8,533,174,81, ब्याज सहित 12% प्रति वर्ष लबित रहने के दौरान दावा दायर करने की तारीख से लेकर पंचाट पुरस्कार मिलने तक एक ही दर पर, किया था।

9. अपीलकर्ता-निगम ने अपने खिलाफ किए गए दावे का दृढ़ता से विरोध किया और आरोप लगाया कि हाइड्रोफोन एक महत्वपूर्ण घटक है, प्रतिवादी ने न केवल पोत के स्ट्रीमर सेक्शन में यूएस निर्मित हाइड्रोफोन को फिट करने की पेशकश की थी, बल्कि वास्तव में इसे फिट भी किया था। अपीलकर्ता का मामला यह था कि दावेदार ने अमेरिका में निर्मित हाइड्रोफोन की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया था और वह कानूनी रूप से ऐसे हाइड्रोफोन से भरे जहाज को 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर सौंपने के लिए बाध्य था जो 9 जुलाई, 2001 को समाप्त हो गई थी। अपीलकर्ता का आगे का मामला यह था कि इसकी आवश्यकता थी। प्रतिवादी द्वारा पहली बार लाइसेंस का उल्लेख तब किया गया था जब 9 जुलाई 2001 को सिंगापुर में जहाज पर अपीलकर्ता के प्रतिनिधि को पत्र दिया गया था, तो प्रतिवादी द्वारा नियत तारीख पर जहाज सौंपने में

विफलता को समझाने का प्रयास किया गया था। अपीलकर्ता-निगम ने दावा किया कि प्रतिवादी ने तब तक लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं किया था और केवल समय विस्तार मांगा था। ऐसा तब हुआ जब अपीलकर्ता-निगम ने प्रतिवादी से यथार्थवादी आधार पर यह बताने के लिए कहा कि किस अवधि के लिए विस्तार की मांग की जा रही है, तब प्रतिवादी ने 26 जुलाई, 2001 के पत्र द्वारा कहा था कि उनकी समझ के अनुसार लाइसेंस है। सितंबर, 2001 के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। चूंकि पक्षकारो के बीच अनुबंध का सार समय था, स्वीकृति पत्र की तारीख से 9 महीने या डिलीवरी से 90 दिनों के भीतर यानी कि 9 जुलाई, 2001 को या उससे पहले विधिवत उन्नत किए गए जहाज को वापस करने में प्रतिवादी की विफलता स्पष्ट थी। अपीलकर्ता-निगम ने तर्क दिया कि, इसके संविदात्मक दायित्व का स्पष्ट उल्लंघन था, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी को निर्धारित नुकसान के भुगतान और जहाज के अतिरिक्त जुड़ाव के लिए उत्तरदायी बनाया गया था।

10. निगम ने मामले की वास्तविक स्थिति में अप्रत्याशित घटना खंड के आह्वान पर भी विवाद किया, खासकर जब उपकरण के लिए लाइसेंस हासिल करना पक्षकारो के बीच अनुबंध का हिस्सा नहीं था, हाइड्रोफ़ोन का प्रकार और निर्माण निर्धारित करना यह प्रतिवादी की एकमात्र जिम्मेदारी थी। अपीलकर्ता-निगम के अनुसार, ट्विन टावरों पर आतंकवादी हमला अनुबंध के बाद की अवधि का मामला था क्योंकि हमले के समय तक अनुबंध के

तहत जहाज की डिलीवरी की तारीख बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। यह भी तर्क दिया गया कि अनुबंध के पूरा होने में देरी पूरी तरह से प्रतिवादी के लिए जिम्मेदार थी, जिसे जब अपीलकर्ता-निगम द्वारा भूकंपीय सर्वेक्षण पोत पेजवाक में उपयोग किए गए एम-2 हाइड्रोफोन की प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, तो उसने सुझाव दिया कि अपीलकर्ता- निगम को इसे सीधे एनआईओसी से प्राप्त करना चाहिए जिससे अपीलकर्ता-निगम को अपने स्वयं के खर्च पर एम-2 हाइड्रोफोन के मापदंडों को सत्यापित करने के लिए ओस्लो में एक प्रतिनिधि भेजने के लिए मजबूर किया जा सके। यह दावा किया गया कि एक बार प्रतिवादी ने अपीलकर्ता-निगम को सूचित किया कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने अंतत: लाईसेंस को अस्वीकार कर दिया है, अपीलकर्ता-निगम के पास यूएस निर्मित हाइड्रोफोन के स्थान पर कनाडाई एम-2 हाइड्रोफोन द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, जिसके परिणामस्वरूप काफी प्रयास के बाद 6 मई, 2002 को जहाज को निगम को वापस देरी से सौंप दिया गया।

11. पक्षकारो की दलीलों पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने निर्धारण के लिए निम्नलिखित मुद्दे तय किए:

(1) क्या नेस्सी-4 स्ट्रीमर में प्रयुक्त हाइड्रोफोन की राष्ट्रीय उत्पत्ति, पक्षकारो के बीच संपर्क का एक भौतिक शब्द था?

(2) क्या प्रतिवादी द्वारा यूएस जियोप्वाइंट हाइड्रोफोन के स्थान पर कनाडाई एम-2 हाइड्रोफोन के प्रतिस्थापन की अनुमति देने से इनकार करना उचित था?

(3) क्या दावेदार की अप्रत्याशित घटना की घोषणा अनुबंध की शर्तों के तहत उचित थी?

(4) क्या संपर्क के निष्पादन में कोई देरी हुई?

(5) यदि बिंदु क्रमांक 4 का उत्तर सकारात्मक है तो ऐसी देरी के लिए कौन जिम्मेदार है?

(6) यदि बिंदु संख्या 4 का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या दावेदार क्षतिपूर्ति का हकदार है?

(7) क्या प्रतिवादी 491,000 अमेरिकी डॉलर की राशि को देय राशि में से पूर्ण या आंशिक रूप से समायोजित करने का हकदार था, जैसा कि बयान के पैरा 30 में बताया गया है?

(8) क्या प्रतिवादी अनुबंध के प्रावधानों के तहत समान अवधि के लिए परिसमाप्त क्षति और अतिरिक्त निहित शुल्क दोनों का हकदार है?

12. न्यायाधिकरण ने जो निर्णय दिया और अंक संख्या 1 प्रकाशित किया, उसका उत्तर नकारात्मक धारणा में दिया गया था कि चूंकि हाइड्रोफोन की पसंद बोली लगाने वालों पर छोड़ दी गई थी, बशर्ते कि

उपकरण इस उद्देश्य के लिए निर्धारित विनिर्देशों को पूरा करते हों और चूंकि शर्तें हाइड्रोफ़ोन के निर्माण या उत्पत्ति के देश को इंगित नही किया, ऐसे हाइड्रोफ़ोन की राष्ट्रीय उत्पत्ति पक्षकारो के बीच अनुबंध की एक भौतिक शर्त नहीं थी।

13. मुद्दा संख्या 2, हालांकि, न्यायाधिकरण द्वारा सकारात्मक में उत्तर दिया गया था, जिसने यह विचार किया था कि एक बार जब प्रतिवादी ने विकल्प चुन लिया और यू.एस. में बने हाइड्रोफोन की आपूर्ति करने के लिए अनुबंध किया, तो अपीलकर्ता-निगम अनुबंधित उपकरणों की आपूर्ति पर जोर देने का हकदार था। मध्यस्थों ने आगे कहा कि एक बार जब प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को सूचित कर दिया था कि अमेरिका निर्मित हाइड्रोफोन का विकल्प बंद हो गया है, तो बाद में इस बात पर जोर देना उचित नहीं था कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ लाइसेंस के अनुरोध को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी के खिलाफ अंक संख्या 3 का फैसला करते हुए कहा कि अनुबंध में उल्लिखित कोई भी घटना नहीं हुई थी और चूंकि अनुबंध के पक्ष अमेरिका से संबंधित नहीं थे, इसलिए प्रतिवादी द्वारा अप्रत्याशित घटना खंड को वैध रूप से लागू नहीं किया जा सकता था। .

14. अनुबंध के प्रदर्शन में देरी के सवाल और अंक संख्या 4 से 8 में शामिल इसके परिणामों से निपटते हुए, मध्यस्थों ने माना कि प्रतिवादी-

दावेदार ने निर्धारित समय सीमा के भीतर संविदात्मक दायित्वों का प्रदर्शन पूरा कर लिया था और होता लेकिन अमेरिकी लाइसेंस की आवश्यकता के लिए जहाज को 9 जुलाई, 2001 को अपीलकर्ता को सौंप दिया गया, ऐसी स्थिति में अप्रत्याशित घटना खंड को लागू करने या समय के विस्तार की मांग करने या कनाडाई हाइड्रोफोन की पेशकश करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर भी तथ्य यह है कि प्रतिवादी ने जहाज को समय पर अपीलकर्ता-निगम को वापस नहीं सौंपा था। न्यायाधिकरण ने तब जांच की कि क्या प्रतिवादी 9 जुलाई 2001 और 6 मई 2002 के बीच पूरी देरी के लिए जिम्मेदार था जब पोत को वास्तव में वापस कर दिया था। न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी की ओर से इस तर्क को खारिज कर दिया कि अनुबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने से अनुबंध के खंड 14 और 16 के तहत अपीलकर्ता में निहित अधिकारों को माफ करने का प्रभाव पड़ेगा। न्यायाधिकरण ने माना कि छूट स्पष्ट होनी चाहिए या तथ्यात्मक स्थिति में छूट देने के इरादे का आवश्यक निहितार्थ होना चाहिए। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने कहा कि केवल समय का विस्तार अनुबंध के खंड 15 और 16 से मिलने वाले अधिकारों की छूट का संकेत नहीं देता है। ऐसा कहने के बाद न्यायाधिकरण ने माना कि चूंकि प्रतिवादी ने 24 अक्टूबर 2001 को ही अपीलकर्ता निगम को अनौपचारिक रूप से सूचित कर दिया था कि वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ लाइसेंस के लिए अनुरोध को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं रखता है और इसलिए 25 अक्टूबर 2001 के

एक पत्र के माध्यम से कनाडाई हाइड्रोफोन के संबंध में अंतिम विवरण विधिवत प्रदान किए गए, प्रतिवादी को निर्णय लेने के लिए कुछ समय स्वीकार करते हुये, 21 अक्टूबर 2001 के बाद की देरी के लिए प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका। न्यायाधिकरण ने पाया कि उस निष्कर्ष ने प्रतिवादी द्वारा परिसमाप्त क्षति के लिए काटी गई राशि को प्रभावित नहीं किया क्योंकि 10% तक सीमित कैपिंग प्रावधान 31 अक्टूबर, 2001 तक की देरी के लिए देय राशि से कम था। जहां तक अतिरिक्त निहित शुल्क का संबंध है, मध्यस्थों ने माना कि 1 नवंबर, 2001 से मार्च 22, 2002 की अवधि के लिये 2,445,246.54 अमेरिकी डॉलर की कटौती अपीलकर्ता-निगम द्वारा गलत तरीके से की गई थी, जो प्रतिवादी पंचाट में दर्शाई गई दर पर ब्याज के साथ अपीलकर्ता से ब्याज प्राप्त करने का हकदार था।

15. भारतीय कानून के तहत कर कानून में बदलाव या करों का भुगतान न करने पर आधारित कटौती के संबंध में, न्यायाधिकरण ने माना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसकी अनुमति नहीं है, विशेष रूप से जब अनुबंधित कार्य को सिंगापुर में प्रतिवादी दावेदार की जहाज मरम्मत इकाई में निष्पादित और पूरा किया जाना था और इसी तरह पूर्ण किए गए जहाज को अपीलकर्ता निगम को सौंपना था। कार्य का कोई भी हिस्सा सिंगापुर के बाहर नहीं किया गया है और किसी भी कर का भुगतान न करने के कारण कोई कटौती नहीं की जा सकती है। मध्यस्थों ने माना कि

चूंकि भारतीय आयकर अधिनियम के तहत कोई कर आकर्षित नहीं होता है, इसलिए कीमत में उक्त कर घटक शामिल नहीं हो सकता है। मध्यस्थों ने तदनुसार माना कि दो मामलों में की गई कटौती, यूएस $ 410,641.20 और यूएस $ 80,530.10 की भी कानून या अनुबंध द्वारा अनुचित और अवांछित थी।

16. मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ता निगम ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत एक याचिका दायर की, जो विफल रही और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई, लेकिन ओएसए नंबर 241/2006 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पंचाट से भविष्य के वादकालीन को हटाने की सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। खंडपीठ के समक्ष अपीलकर्ता-निगम की ओर से तीन स्तरीय तर्क दिया गया ।सबसे पहले, यह तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण ने यह मानकर गलती की है कि 14 सितंबर 2001 और 21 मार्च 2002 के बीच की देरी के लिए प्रतिवादी कंपनी जिम्मेदार नहीं थी। दूसरे, यह तर्क दिया गया कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का यह मानना सही नहीं था कि अपीलकर्ता द्वारा करों के प्रति की गई कटौती कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं थी। तीसरा यह तर्क दिया गया कि लंबित मुकदमे और भविष्य के हित के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया फैसला उचित नहीं था।

जबकि खंडपीठ ने पहले दो तर्कों को खारिज कर दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी ने पहले एक बयान दिया है। उच्च न्यायालय ने लंबित ब्याज को माफ कर दिया और उस सीमा तक पुरस्कार में संशोधन पर सहमति व्यक्त की। उच्च न्यायालय ने माना कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि 16 अक्टूबर और 21 मार्च 2002 के बीच की देरी प्रतिवादी के लिए जिम्मेदार नहीं है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार पर आधारित थी जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, उच्च न्यायालय के अनुसार, करों के भुगतान के लिए कटौती को भी मध्यस्थों द्वारा उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।

17. वर्तमान अपील मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पुरस्कार और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की सत्यता पर सवाल उठाती है, जैसा कि इस आदेश की शुरुआत में देखा गया है।

18. हमने पक्षकारो के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है, जिन्होंने हमें मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले, पार्टियों के बीच निष्पादित अनुबंध के प्रावधानों और उनके बीच हुए पत्राचार के बारे में बताया है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुधार के बाद जहाज को निगम को लौटाने में देरी हुई। संविदात्मक समय-सारणी के अनुसार जहाज को 9 जुलाई 2001 तक निगम को वापस आ जाना चाहिए था, जिसे 9 महीने और

28 दिनों की देरी के बाद 6 मई 2002 को ही निगम को लौटाया गया। इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है, यह पक्षकारो के बीच विवाद का सार है। अपीलकर्ता-निगम के अनुसार देरी पूरी तरह से प्रतिवादी के लिए जिम्मेदार है, जबकि प्रतिवादी के अनुसार देरी के लिए अपीलकर्ता जिम्मेदार है। मध्यस्थों ने उनके सामने रखी गई सामग्री की जांच करने के बाद इस आशय का निष्कर्ष दर्ज किया कि 10 जुलाई 2001 और 31 मार्च 2001 के बीच की देरी पूरी तरह से प्रतिवादी के लिए जिम्मेदार थी। उस निष्कर्ष को प्रतिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी और न ही यह हमारे समक्ष चुनौती के अधीन है। मध्यस्थों ने अपने द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के आधार पर अपीलकर्ता-निगम को पक्षकारो के बीच निष्पादित अनुबंध के खंड 16 के तहत परिसमाप्त क्षति के अलावा खंड 14 के तहत अतिरिक्त सगाई शुल्क की अनुमति दी है। लेकिन 1 नवंबर, 2001 और 22 मार्च, 2002 के बीच की अवधि के लिए, जो 4 महीने और 22 दिनों तक आती है, मध्यस्थों ने देरी को अपीलकर्ता-निगम के लिए जिम्मेदार पाया है। इस अवधि के संबंध में निगम द्वारा की गई कटौती को मध्यस्थों द्वारा गलत ठहराया गया है और राशि को प्रतिवादी-कंपनी के पक्ष में जारी करने का निर्देश दिया गया है। पंचाट की अवधि और उसके लिए काटी गई राशि का विवरण निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है:

"परिणाम में हमारी राय है कि 1 नवंबर, 2001 से 23 मार्च, 2002 तक की अवधि को छोड़कर, जिसके लिए दावेदार के चालान से कटौती की गई है, दावेदार के दावे से की गई शेष कटौती के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है 1 नवंबर, 2001 से 22 मार्च, 2002 (4 महीने + 22 दिन) की अवधि के संबंध में कटौती यूएस $ 2,445,246.53 की राशि बनती है, जिसे दावेदार ब्याज सहित प्रतिवादी से इसके बाद संकेतित दर से प्राप्त करने का हकदार होगा।"

19. हमारी राय में, 1 नवंबर, 2001 और 22 मार्च, 2002 के बीच 4 महीने और 22 दिनों की उपरोक्त अवधि में चार अलग-अलग अंतराल शामिल हैं। इन चार अंतरालों में से पहला अंतराल 1 नवंबर, 2001 और 26 नवंबर, 2001 के बीच की अवधि है, जो अपीलकर्ता-निगम द्वारा अंतिम निर्णय लेने के लिए लिया गया था कि इस मुद्दे के लिए अमेरिकी अधिकारियों को लाईसेंस के लिये आवेदन किया जाना चाहिए या नहीं। दूसरे अंतराल में 27 नवंबर, 2001 और 7 जनवरी, 2002 के बीच प्रतिवादी-दावेदार द्वारा आवेदन करने में लिया गया समय शामिल है, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं। लाइसेंस देने के लिए आवेदन प्रतिवादी द्वारा केवल 8 जनवरी, 2002 को दायर किया गया था। तीसरे अंतराल में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत के लिए बनाये गये हाइड्रोफोन की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने को औपचारिक रूप से अस्वीकार करने के लिए 8 जनवरी, 2002 और 7 मार्च, 2002 के बीच लिया

गया समय शामिल है। चौथे अंतराल में प्रतिवादी-दावेदार द्वारा 8 मार्च, 2002 और 21 मार्च, 2002 के बीच अमेरिकी अधिकारियों के निर्णय को बताने में लिया गया समय शामिल है। यह सामान्य आधार है कि अमेरिकी अधिकारियों ने 8 मार्च 2002 को लाइसेंस देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, उक्त अस्वीकृति अपीलकर्ता-निगम को 22 मार्च, 2002 को ही सूचित की गई थी।

20. मध्यस्थों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों से जिसमें हमें हस्तक्षेप या असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता है, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता-निगम 24 अक्टूबर, 2001 और 26 नवंबर, 2001 के बीच मामले में निर्णय लेने में देरी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था। मध्यस्थों ने पाया है और, हमारी राय में, यह सही है कि प्रतिवादी-दावेदार को इसके पत्र दिनांक 24 अक्टूबर, 2001 ने अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से सूचित किया कि इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के साथ आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। यहां तक कि कैनेडियन हाइड्रोफोन के बारे में विवरण भी अपीलकर्ता को 25 अक्टूबर, 2001 के एक पत्र के संदर्भ में प्रदान किए गए थे। मध्यस्थों ने माना है कि कोई औपचारिक आवेदन किया जाना चाहिए या नहीं, यह निर्णय लेने में देरी के लिये और प्रतिवादी द्वारा प्राप्त औपचारिक अस्वीकृति के लिये केवल अपीलकर्ता-निगम इसके लिए जिम्मेदार था। हमारी राय में, उस निष्कर्ष में कोई कानूनी दोष, दुर्बलता या विकृति नहीं है जिसकी हम

पुष्टि करते हैं। प्रथम अंतराल के लिए अपीलकर्ता-निगम द्वारा की गई कटौती, जिसमें 1 नवंबर, 2001 और 25 नवंबर, 2001 के बीच की अवधि शामिल है, दोनों दिन शामिल हैं, इसलिए बरकरार नहीं रखी जा सकती है और उस सीमा तक मध्यस्थ पुरस्कार को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

21. यह हमें 26 नवंबर, 2001 के बीच की अवधि के दूसरे अंतराल पर लाता है - वह तारीख जब अपीलकर्ता-निगम ने लाइसेंस देने के लिए औपचारिक आवेदन करने के लिए निर्देश जारी किए थे और 8 जनवरी, 2002 - जब ऐसा आवेदन प्रतिवादी- कंपनी द्वारा वास्तव में किया गया था 27 नवंबर, 2001 से 7 जनवरी, 2002 तक की यह अवधि कुल मिलाकर 42 (बयालीस) दिन बनती है, जिसका श्रेय प्रतिवादी-दावेदार को दिया जाना चाहिए, जो वास्तव में इस मामले में परिश्रमपूर्वक और उचित तत्परता के साथ कार्य कर सकता था और करना भी चाहिए था। इसे सहजता से लेते हुए, और यदि हम कुछ हद तक अनिच्छा से ऐसा कह सकते हैं। हम मध्यस्थ न्यायाधिकरण में शामिल प्रतिष्ठित न्यायविदों की प्रतिष्ठा और विद्वता के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ यह कहने से नहीं रह सकते कि न्यायाधिकरण इस पहलू की सराहना करने में विफल रहा, इसलिए एक स्पष्ट त्रुटि हुई जिसके कारण न्याय की हानि हो गई। विलंब के लिए अपीलकर्ता निगम को जिम्मेदार ठहराने के लिए न्यायाधिकरण द्वारा

अपनाए गए परीक्षण को प्रतिवादी पर भी लागू किया जाना चाहिए था, क्योंकि मामले को दबाने के बजाय सही कार्रवाई करने में विफलता के कारण जहाज को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। उससे भी अधिक जो नितांत आवश्यक था।

22. 8 जनवरी, 2002 और 8 मार्च, 2002 के बीच की अवधि, जिसमें तीसरा अंतराल शामिल है, जिसके दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने निर्णय लिया कि लाइसेंस देने के लिए आवेदन को अपीलकर्ता-निगम के खिलाफ सही तरीके से गिना गया है क्योंकि यह निगम के कहने पर था कि एक औपचारिक आवेदन किया गया था। अनुरोध के निपटान के लिए अमेरिकी अधिकारियों द्वारा खर्च किए गए समय को तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादी-दावेदार के लिए जिम्मेदार या गिना नहीं जा सकता, जिसने अपीलकर्ता को ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ सलाह दी थी। इसलिए, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने सही माना कि इस अवधि के लिए कटौती उचित नहीं थी।

23. यह हमें चौथे और आखिरी अंतराल पर छोड़ता है जिसमें 8 मार्च, 2002 और 22 मार्च, 2002 के बीच की अवधि शामिल है जब आवेदन की अस्वीकृति अपीलकर्ता-निगम को बताई गई थी। हमारी राय में, ऐसा कोई वैध कारण नहीं है कि इस अवधि को प्रतिवादी के खिलाफ क्यों नहीं गिना जाना चाहिए, जिसे ऐसा करने में लगभग दो सप्ताह लगने के बजाय

अपीलकर्ता-निगम को तुरंत अस्वीकृति बतानी चाहिए थी। सारांश में; 4 महीने और 22 दिनों की अवधि, जिसे मध्यस्थों ने अपीलकर्ता-निगम के लिए जिम्मेदार ठहराया है, को पहले अंतराल सहित 42 दिन और चौथे अंतराल सहित 14 दिन घटाकर कुल 56 दिन करना होगा। परिणामस्वरूप, ऊपर उल्लिखित 56 दिनों के लिए अपीलकर्ता-निगम द्वारा की गई कटौती की पुष्टि की जानी चाहिए, और मध्यस्थों द्वारा दिए गए निर्णय को उस सीमा तक संशोधित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिवादी-कंपनी को दी जाने वाली राशि आनुपातिक आधार पर कम हो जाएगी।

24. हम इस स्तर पर प्रतिवादी की ओर से आग्रह किए गए विवाद से निपट सकते हैं कि मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के आधार पर सीमित है, इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह तर्क दिया गया कि जिन आधारों पर न्यायालय को मध्यस्थ पुरस्कार में हस्तक्षेप करने का अधिकार है उनमें से कोई भी आधार मौजूदा मामले में मौजूद नहीं है। वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया गया कि भले ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष सिद्ध तथ्यों पर एक विपरीत दृष्टिकोण संभव हो, न्यायालय, किसी भी बाध्यकारी कारण के अभाव में, मध्यस्थों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जैसे कि वह अपील में

न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये पंचाट में बैठा हो। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 में लिखा है:

*34. मध्यस्थ पंचाट को रद्द करने के लिए आवेदन.-(1) किसी मध्यस्थ पंचाट के खिलाफ अदालत का सहारा केवल उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के अनुसार ऐसे पंचाट को रद्द करने के लिए एक आवेदन द्वारा किया जा सकता है।

(2) किसी मध्यस्थ पंचाट को न्यायालय द्वारा केवल तभी रद्द किया जा सकता है, यदि-

(ए) आवेदन करने वाला पक्ष सबूत प्रस्तुत करता है कि-

(i) एक पार्टी किसी अक्षमता के अधीन थी, या

(ii) मध्यस्थता समझौता उस कानून के तहत वैध नहीं है जिसके लिए पक्षकारो ने इसे अधीन किया है या, उस पर किसी भी संकेत के अभाव में, उस समय लागू कानून के तहत वैध नहीं है; या

(।।।) आवेदन करने वाले पक्ष को मध्यस्थ की नियुक्ति या मध्यस्थ कार्यवाही की उचित सूचना नहीं दी गई थी या अन्यथा वह अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था; या

(iv) मध्यस्थ पंचाट ऐसे विवाद से निपटता है जिस पर विचार नहीं किया गया है या जो मध्यस्थता में प्रस्तुत करने की शर्तों के

अंतर्गत नहीं आता है, या इसमें मध्यस्थता में प्रस्तुत करने के दायरे से बाहर के मामलों पर निर्णय शामिल हैं:

बशर्ते, यदि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों पर निर्णयों को इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों से अलग किया जा सकता है, तो मध्यस्थता पंचाट का केवल वह हिस्सा जिसमें मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए मामलों पर निर्णय शामिल हैं, को अलग रखा जा सकता है; या

(v) मध्यस्थ न्यायाधिकरण या मध्यस्थ प्रक्रिया की संरचना पक्षकारो के समझौते के अनुसार नहीं थी, जब तक कि ऐसा समझौता इस भाग के प्रावधान के साथ संघर्ष में न हो, जिससे पक्षकार अपमानित नहीं हो सकतीं, या ऐसा समझौता विफल होने पर, इस भाग के अनुसार नहीं था; या

(बी) अदालत ने पाया कि-

(i) विवाद की विषय वस्तु फिलहाल लागू कानून के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है, या

(i) मध्यस्थ निर्णय भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है।

स्पष्टीकरण.-उपखंड (ii) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी संदेह से बचने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि एक पुरस्कार भारत की सार्वजनिक नीति के साथ टकराव में है यदि पंचाट का निर्माण प्रेरित या प्रभावित या धोखाधड़ी से या भ्रष्टाचार द्वारा या धारा 75 या धारा 81 के उल्लंघन द्वारा किया गया था।

25. यह सच है कि धारा 34(2)(ए) के तहत गिनाए गए किसी भी आधार को मध्यस्थ पंचाट पर हमला करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष और हमारे समक्ष भी यही आग्रह किया गया था कि मध्यस्थों द्वारा दिया गया निर्णय "भारत की सार्वजनिक नीति" के विपरीत था, जो कि धारा 34(2)(बी)(ii) के तहत मान्यता प्राप्त आधार है (उपरोक्त)। अभिव्यक्ति "भारत की सार्वजनिक नीति" ओएनजीसी लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड (2003) 5 एससीसी 705 में इस न्यायालय के समक्ष व्याख्या के ली आई और, मामले पर कानून की व्यापक समीक्षा के बाद, निर्णय के पैरा 31 में निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया था :

"31. इसलिए, हमारे विचार में, संदर्भ में धारा 34 में प्रयुक्त वाक्यांश "भारत की सार्वजनिक नीति" को व्यापक अर्थ देने की आवश्यकता है। यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक नीति की अवधारणा कुछ ऐसे मामले को दर्शाती है जो जनता की भलाई और सार्वजनिक हित

से संबंधित है । लोक अच्छाई या सार्वजनिक हित में क्या है या लोक अच्छाई या सार्वजनिक हित के लिए क्या हानिकारक या नुकसानदेह होगा, समय-समय पर भिन्न होता है। हालाँकि, जो पंचाट दिया जाता है, वह स्पष्ट रूप से उल्लंघन है वैधानिक प्रावधानों को सार्वजनिक हित में नहीं कहा जा सकता है। इस तरह के पंचाट/निर्णय/आदेश से न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए, हमारे विचार में रेनुसागर मामले में "सार्वजनिक नीति" शब्द को दिए गए संकीर्ण अर्थ के अलावा, यह माना जाना आवश्यक है कि यदि पंचाट स्पष्ट रूप से अवैध है तो उसे रद्द किया जा सकता है। परिणाम यह होगा कि - यदि यह इसके विपरीत है तो पंचाट रद्द किया जा सकता है:

(ए) भारतीय कानून की मौलिक नीति, या

(बी) भारत का हित; या

(सी) न्याय या नैतिकता, या

(डी) इसके अलावा, यदि यह स्पष्ट रूप से अवैध है।

अवैधता को मामले की जड़ तक जाना चाहिए और यदि अवैधता तुच्छ प्रकृति की है तो यह नहीं माना जा सकता कि पंचाट सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। पंचाट को रद्द भी किया जा सकता है

यदि यह इतना अनुचित और असंगत है कि यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दे। इस तरह का पंचाट सार्वजनिक नीति के विपरीत है और इसे रद्द घोषित किया जाना आवश्यक है।"

26. फिर 'भारतीय कानून की मौलिक नीति' क्या बनेगी, यह प्रश्न है। सॉ पाइप्स लिमिटेड (उपरोक्त) का निर्णय उस पहलू को विस्तृत नहीं करता है। फिर भी, हमारी राय में, अभिव्यक्ति में इस देश में न्याय प्रशासन और कानून के प्रवर्तन के लिए आधार प्रदान करने वाले सभी मौलिक सिद्धांत शामिल होने चाहिए। "भारतीय कानून की मौलिक नीति" अभिव्यक्ति के अभिप्राय को विस्तृत रूप से गिनाए बिना, हम तीन विशिष्ट और मौलिक न्यायिक सिद्धांतों का उल्लेख कर सकते हैं जिन्हें आवश्यक रूप से भारतीय कानून की मौलिक नीति के एक भाग और पार्सल के रूप में समझा जाना चाहिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि प्रत्येक निर्णय में, चाहे वह न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा हो, जो किसी नागरिक के अधिकारों को प्रभावित करता है या किसी नागरिक परिणाम की ओर ले जाता है, संबंधित न्यायालय या प्राधिकारी वह मामले में अपनाने के लिए बाध्य है जिसे कानूनी भाषा में न्यायिक दृष्टिकोण कहा जाता है। न्यायिक दृष्टिकोण अपनाने का कर्तव्य न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति से उत्पन्न होता है, जिसे संबंधित मंचों पर अलग से या अतिरिक्त रूप से लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह याद

रखना चाहिए कि न्यायिक और अर्धन्यायिक निर्धारण में न्यायिक दृष्टिकोण का महत्व इस तथ्य में निहित है कि जब तक न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो उनके सामने पक्षकारो के अधिकारों या दायित्वों को प्रभावित करते हैं, न्यायिक दृष्टिकोण के प्रति निष्ठा दिखाते हैं, वे मनमाने, मनमौजी या सनकी तरीके से कार्य नहीं कर सकते। न्यायिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि प्राधिकारी सद्भावनापूर्वक कार्य करता है और विषय से निष्पक्ष, उचित और वस्तुनिष्ठ तरीके से निपटता है और उसका निर्णय किसी भी बाहरी विचार से प्रेरित नहीं होता है। इस अर्थ में न्यायिक दृष्टिकोण उन खामियों और दोषों के खिलाफ एक जाँच के रूप में कार्य करता है जो न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के निर्णय को चुनौती के लिए असुरक्षित बना सकते हैं। रिज बनाम बाल्डविन [1963 2 ऑल ईआर 66] में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इस सवाल पर विचार कर रहा था कि क्या नगर निगम अधिनियम, 1882 की धारा 191 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करने में एक वॉच कमेटी को न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता थी। बहुमत का निर्णय यह था कि उसे न्यायिक रूप से कार्य करना था और चूंकि अपीलकर्ता को कोई विशिष्ट आरोप प्रस्तुत किए बिना बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था, इसलिए यह अमान्य था। अपीलकर्ता के इस तर्क से निपटते हुए कि वॉच कमेटी को न्यायिक रूप से कार्य करना था, लॉर्ड रीड ने एटकिन

एल.जे. द्वारा [1924] 1 केबी पृष्ठ 206, 207 में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया:

> जहां भी व्यक्तियों के किसी निकाय के पास विषयों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्न निर्धारित करने का कानूनी अधिकार है, और न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य है, अपने कानूनी अधिकार से अधिक कार्य करने पर, वे इन रिट में प्रयुक्त किंग्स बेंच डिवीजन के नियंत्रण क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।"

27. ए.सी. कंपनीज़ लिमिटेड बनाम पी.एन. शर्मा और अन्य. (एआईआर 1965 एससी 1595) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने लॉर्ड रीड द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर भरोसा किया था, जहां गजेंद्रगडकर, मुख्य न्यायाधिपति, ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा:

> "दूसरे शब्दों में, लॉर्ड रीड के फैसले के अनुसार, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता उस निर्णय की प्रकृति से आती है, जिस पर निगरानी समिति को धारा 191(4) के तहत पहुंचने के लिए अधिकृत किया गया था। यह इस प्रकार देखा जा सकता है कि वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना है और न्यायिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना व्यापक हो गया है, और परिणामस्वरूप, रिट क्षेत्राधिकार का क्षितिज भी इसी माप में बढ़ाया गया है। क्या

हमारे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी विवादित आदेश को संशोधित किया जा सकता है, इस निर्णय में लॉर्ड रीड द्वारा निर्धारित परीक्षण से काफी सहायता मिल सकती है।"

28. भारतीय कानून की नीति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण और वास्तव में मौलिक यह सिद्धांत है कि एक न्यायालय और एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को भी, अपने समक्ष पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करते समय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा करना चाहिए। प्रसिद्ध 'ऑडी अल्टरम पार्टम' नियम के अलावा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक पहलू यह है कि मामले का निर्णय करने वाले न्यायालय/प्राधिकरण को एक या दूसरे तरीके से विचार करते समय अपने दिमाग को संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू करना चाहिए। दिमाग का प्रयोग न करना एक दोष है जो किसी भी निर्णय के लिए घातक है। मन के प्रयोग को मन के प्रकटीकरण द्वारा सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित किया जाता है और मन का प्रकटीकरण न्यायालय या प्राधिकरण द्वारा लिए जा रहे निर्णय के समर्थन में कारणों को दर्ज करके सर्वोत्तम रूप से किया जाता है। उस दृष्टि से, यह आवश्यकता है कि एक न्यायिक प्राधिकारी को अपना दिमाग लगाना चाहिए, यह दृष्टिकोण हमारे न्यायशास्त्र में इतनी गहराई से अंतर्निहित है कि इसे भारतीय कानून की मौलिक नीति के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

हमारे न्यायशास्त्र में यह गहराई से अंतर्निहित है कि इसे भारतीय कानून की मौलिक नीति के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

29. यह सिद्धांत अब कम महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे प्रशासनिक कानून में एक हितकारी न्यायिक मौलिक के रूप में मान्यता दी जाए कि एक निर्णय जो विकृत या इतना तर्कहीन है कि कोई भी उचित व्यक्ति उस पर नहीं पहुंचा होगा, उसे कानून की अदालत में बरकरार नहीं रखा जाएगा। निर्णयों की विकृति या अतार्किकता का परीक्षण वेडनसबरी के तर्कसंगतता के सिद्धांत की कसौटी पर किया जाता है। तर्कसंगतता के मानकों से कमतर निर्णयों को अक्सर उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार में कानून की अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन वैधानिक प्रक्रियाओं में भी, जहां भी ये उपलब्ध हैं, चुनौती दी जा सकती है।

30. हमारे लिए भारतीय कानून की मौलिक नीति का गठन करने वाली विस्तृत गणना का प्रयास करना न तो आवश्यक है और न ही उचित है और न ही अभिव्यक्ति को किसी परिभाषा के दायरे में रखना संभव है। मामले के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मध्यस्थ अपने सामने साबित तथ्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालने में विफल रहते हैं जो निकाला जाना चाहिए था या यदि उन्होंने कोई ऐसा निष्कर्ष निकाल लिया है जो प्रथमदृष्टया अस्थिर है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की हानि, निर्णय तब भी जब एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता है जो काफी

स्वतंत्रता का आनंद लेता है और पंचाट देने में जोड़ों पर खेलता है, चुनौती के लिए खुला होगा और इसे खारिज या संशोधित किया जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपमानजनक हिस्सा अन्य से अलग है या नहीं ।

31. चूंकि मध्यस्थों ने देरी के लिए अपीलकर्ता-निगम को जिम्मेदार ठहराने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर, 2001 और 21 मार्च, 2002 के बीच की पूरी अवधि को एक साथ जोड़ दिया, उन्होंने एक त्रुटि की जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात हो गया, इस तथ्य के अलावा कि वे ऐसे सिद्ध तथ्यों की सराहना करने और तार्किक रूप से निष्कर्ष निकालने में विफल रहे। इसलिए, हमें प्रतिवादी की ओर से आग्रह किए गए इस तर्क को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे द्वारा बताई गई कमजोरियों के बावजूद मध्यस्थ पंचाट में खलल नहीं डाला जाना चाहिए।

32. यह हमें अंतिम निवेदन पर लाता है कि भुगतान न किए गए करों के कारण कटौती की अनुमति प्रतिवादी-मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दी जानी चाहिए थी। न्यायाधिकरण ने, हमारी राय में, सही ढंग से माना है कि काम का कोई भी हिस्सा सिंगापुर के बाहर नहीं किया गया था, जिसे पूर्व-निर्धारित कीमत पर टर्नकी आधार पर निष्पादित किया जाना था। हमारी राय में, मध्यस्थों ने सही माना है कि भारतीय आयकर अधिनियम के तहत कोई कर देय नहीं है, जिससे निगम को ऐसे करों का भुगतान न करने के

कारण उस खाते पर कोई भी राशि काटने का अधिकार मिल सके। उस सीमा तक पंचाट के लिए चुनौती विफल होनी चाहिए और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

33. परिणामस्वरूप, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल इस हद तक कि 4 महीने और 22 दिनों की अवधि में से, जिसे मध्यस्थों ने अपीलकर्ता-निगम के लिए जिम्मेदार ठहराया है, 56 दिनों की अवधि, जिसमें पहले अंतराल के 42 दिन शामिल है और फैसले में उल्लिखित दूसरे के 14 दिन कम कर दिए जाएंगे। परिणामस्वरूप, 56 दिनों की उक्त अवधि के लिए अपीलकर्ता-निगम द्वारा की गई कटौती की पुष्टि की जाएगी और मध्यस्थों द्वारा दिए गए पंचाट को प्रतिवादी को देय राशि में आनुपातिक कमी के साथ उस सीमा तक संशोधित किया जाएगा। कोई लागत नहीं.

निधि जैन

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।